

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13115/2021

में

डी. बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 198/2024

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, घूघरा घाटी, अजमेर

---अपीलकर्ता-प्रतिवादी

बनाम

1. कुलदीप जैमन पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जैमन, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी मकान नंबर 121, वार्ड नंबर 10, खासा मोहल्ला, खास स्कूल के पास, अलवर 301001 (राज.)
मोबाइल 7891278718

---प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता

2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय,
जयपुर-302005 के माध्यम से
3. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसका कार्यालय सरकारी
सचिवालय, जयपुर में है

---प्रोफार्मा प्रतिवादी

अपीलकर्ता की ओर से : श्री अमित लुभाया अधिवक्ता के साथ श्री
श्रेयांश जैन अधिवक्ता; सुश्री गरिमा गोथवाल
अधिवक्ता और श्री देवेश बाजोरिया
अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से : श्री शोवित झाझरिया अधिवक्ता के साथ श्री
अंकित कुमार अधिवक्ता और श्री उत्कर्ष दुबे
अधिवक्ता। श्री कुलदीप जैमन प्रतिवादी
संख्या 1 स्वयं उपस्थित।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

06/03/2024

1. पक्षों के विद्वान वकील को सुना गया।
2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.02.2024 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 (दिव्यांग व्यक्ति) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता पर ₹5,00,000/- का जुर्माना लगाया गया है।
3. अनावश्यक विवरणों को हटाकर, प्रतिवादी संख्या 1, जो 100% दृष्टिबाधित है, ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के तहत नियुक्ति के लिए दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन के अनुसरण में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विज्ञापन अपीलकर्ता-राजस्थान लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आरपीएससी' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किया गया था। आरपीएससी ने विकलांगता वाले उम्मीदवारों को यह विकल्प दिया कि वे अपना खुद का लेखक ला सकते हैं या आरपीएससी से यह सुविधा मांग सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 1, जैसा कि स्वीकार किया गया है, ने अपना खुद का लेखक लाने का विकल्प चुना। जैसा कि रिट याचिका में दिए गए तर्कों से पता चलता है, प्रतिवादी संख्या 1 सुबह 9:00 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से इस आधार पर कि प्रतिवादी संख्या 1 विकलांगता प्रमाण पत्र/चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लाया था, उसे सभी आग्रह के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस वजह से प्रतिवादी संख्या 1 को रिट याचिका दायर करनी पड़ी।

4. अपीलकर्ता-आरपीएससी द्वारा दायर जवाब में, रिट याचिका में मांगी गई राहत का विरोध करने के लिए जो मुख्य आधार उठाया गया था, वह यह था कि विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू निर्देशों के तहत उन उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अपना विकलांगता प्रमाण पत्र लाना आवश्यक था। रिट याचिका में मांगी गई राहत का विरोध करने के लिए जवाब में उठाया गया दूसरा आधार यह था कि प्रतिवादी संख्या 1 को परीक्षा की तारीख से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर सूचित करना आवश्यक था जो उसके द्वारा नहीं किया गया था।
5. अपीलकर्ता-आरपीएससी द्वारा उठाए गए रुख को विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप यह विशेष निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी संख्या 1 को अवैध रूप से परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता-आरपीएससी पर ₹5,00,000/- का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
6. अपीलकर्ता-आरपीएससी के विद्वान वकील ने हमारे सामने जोरदार ढंग से और विस्तार से तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक को सूचित करने की विशिष्ट आवश्यकता का पालन नहीं किया कि वह अपना खुद का लेखक लाएगा और जब वह परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो वह अपना विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं लाया। निर्देशों (अपीलकर्ता-आरपीएससी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब के साथ संलग्न अनुबंध आर-1) का जिक्र करते हुए, "श्रुतलेखक (SCRIBE) उपलब्ध कराए जाने संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश" शीर्षक के तहत, विशेष रूप से खंड 10 और 11 का, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्पष्ट निर्देश थे कि विकलांगता वाले उम्मीदवार को परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक को सूचित करना आवश्यक था और उसे विकलांगता प्रमाण पत्र/चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लाना आवश्यक था। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन वह आलसी था क्योंकि उसने सुबह 9:45 बजे ही परीक्षा केंद्र कार्यालय में संपर्क किया, जबकि परीक्षा सुबह 10:00 बजे शुरू होनी थी। अधिकारियों को विकलांग श्रेणी से संबंधित व्यक्ति के रूप में लेखक के साथ आने वाले उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने का

अधिकार था। इसलिए, यदि प्रतिवादी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, तो आरपीएससी पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार की भागीदारी से इनकार करने के परिणामस्वरूप कुछ उल्लंघन हुआ था, लेकिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 20 और 21 में निहित प्रावधानों के अनुसार, मामले को उन प्रावधानों के तहत निपटाया जाना आवश्यक है और केवल उल्लंघन की पुनरावृत्ति के मामले में, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- का अत्यधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जुर्माना लगाते समय, डिफॉल्ट पर जुर्माना/जुर्माना लगाने के संबंध में अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानों को गलत समझा है। यह भी अपीलकर्ता के विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां आरपीएससी के कार्यालय का कथित रूप से परीक्षा में भागीदारी से इनकार करने से कोई लेना-देना था। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि परीक्षा केंद्र आरपीएससी द्वारा प्रशासन की मदद से लगाए जाते हैं और यदि, किसी विशेष परीक्षा केंद्र पर, केंद्र अधीक्षक ने, एक या दूसरे कारण से, विकलांग व्यक्ति को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी थी, तो केवल उस व्यक्ति पर ही दायित्व लगाया जाना चाहिए, न कि आरपीएससी पर। इसलिए, आरपीएससी पर जुर्माना लगाना कानून में उचित नहीं है।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया और प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ता की कार्रवाई को अवैध पाया गया है और, इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा प्रणाली की गलती के कारण, एक विकलांग व्यक्ति ने सार्वजनिक रोजगार का एक अवसर खो दिया, जुर्माना लगाया गया है।

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना, रिकॉर्ड और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता-आरपीएससी द्वारा दायर जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने का कारण बताया गया है

कि प्रतिवादी संख्या 1 ने परीक्षा से पहले किसी भी समय परीक्षा केंद्र पर संपर्क नहीं किया था और/या केंद्र अधीक्षक को अपना खुद का लेखक लाने के बारे में सूचित नहीं किया था और वह अपनी विकलांगता स्थापित करने के लिए कोई विकलांगता प्रमाण पत्र या सबूत भी नहीं लाया था। रिट याचिका के जवाब में, अपीलकर्ता-आरपीएससी द्वारा निम्नलिखित अभिकथन किए गए हैं: अपीलकर्ता-आरपीएससी:

"इस मामले में, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में ही स्वीकार किया है कि उसने परीक्षा केंद्र और/या केंद्र अधीक्षक को परीक्षा से पहले किसी भी समय अपना खुद का लेखक लाने के बारे में सूचित नहीं किया था और वह अपनी विकलांगता स्थापित करने के लिए कोई विकलांगता प्रमाण पत्र या सबूत भी नहीं लाया था।

यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता (रोल नंबर 154572) 27.10.2021 को सुबह 9:45 बजे परीक्षा केंद्र 02-0030 (अलवर) में प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ और केंद्र अधीक्षक से अपने स्वयं के लेखक के साथ नेत्रहीन/कम दृष्टि श्रेणी के तहत उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालांकि, याचिकाकर्ता से उसके विकलांगता/चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध करने पर, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह अपनी विकलांगता का प्रमाण नहीं लाया और एक आवेदन प्रस्तुत किया कि वह इसे दोपहर 2:00 बजे तक प्रदान करेगा। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुबंध आर-2 के रूप में चिह्नित है।"

उपरोक्त के अलावा, परीक्षा तक पहुंच से इनकार करने के कारण के रूप में जवाब में कोई अन्य आधार नहीं बताया गया था।

11. निर्देशों (अपीलकर्ता-आरपीएससी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब के साथ संलग्न अनुबंध आर-1) पर भारी भरोसा किया गया है, विशेष रूप से खंड 10 और 11 जो नीचे पुनरुत्पादित हैं:

"10- ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अपने आवेदन में निश्चिन्ता नहीं भरी है या श्रुतलेखक की सुविधा हेतु केंद्राधीक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से पूर्व ही सूचना नहीं दी है या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, को यह सुविधा देय नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी, जो अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए हैं, उन्हें श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

11- यदि किसी परीक्षा में कतिपय प्रश्न चित्र या आकृति आधारित हैं, तो आयोग उनके प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों को हटाते हुए और इनके स्थान पर नए प्रश्न रखते हुए पृथक से प्रश्न पत्र तैयार करा सकता है, क्योंकि **दृष्टिबाधित (Blind/Low Vision)** परीक्षार्थी ऐसे प्रश्नों को देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार ऐसे **दृष्टिबाधित (Blind/Low Vision)** परीक्षार्थी, जिनको श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जाएगा, उन

परीक्षार्थियों हेतु प्रश्न पत्र अलग से दिए जा सकते हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं कि यह सुविधा प्रत्येक परीक्षा में दी ही जाए जहाँ आयोग द्वारा **दृष्टिबाधित** परीक्षार्थियों के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार कराने का निर्णय लिया जाएगा वहाँ पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में कैटेगरी **Blind/Low Vision** लिखी हुई है, किंतु अभ्यर्थी उस श्रेणी में नहीं आता है अर्थात् वह **दृष्टिबाधित** होने का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे अन्य सामान्य प्रश्न पत्र दिया जाएगा एवं जिसका निर्णय केंद्राधीक्षक स्वयं के स्तर पर करेंगे।“

उपरोक्त खंडों के शाब्दिक पठन पर, यह स्पष्ट है कि निर्देश केवल उन मामलों में लागू थे जहां विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति आरपीएससी से लेखक की सुविधा मांगते हैं। ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होते हैं जहां एक उम्मीदवार अपना खुद का लेखक लाने का फैसला करता है। यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपना खुद का लेखक लाएगा। यदि यह स्वीकृत स्थिति है, तो उपरोक्त निर्देशों में निहित कोई भी प्रावधान ऐसे उम्मीदवार पर लागू नहीं होता है जो विकलांगता से पीड़ित है और उसने अपना खुद का लेखक लाना चुना है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे ध्यान में कोई अन्य निर्देश नहीं लाया गया है जो यह दर्शाता है कि यदि कोई उम्मीदवार अपना खुद का लेखक लाना चुनता है, तो उस स्थिति में भी, उसे परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक को सूचित करना आवश्यक है। वास्तव में, खंड 10 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि वे उम्मीदवार, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में विकलांगता का खुलासा नहीं किया है या परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक को लेखक की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे सुविधा के हकदार नहीं होंगे। खंड 10 में इस्तेमाल किया गया शब्द, "सुविधा" आरपीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली लेखक की सुविधा को संदर्भित करता है और यह स्पष्ट रूप से ऐसे मामले में कोई आवेदन नहीं है जहां उम्मीदवार अपना खुद का लेखक लाता है।

12. एक उम्मीदवार के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता, जो अपना खुद का लेखक लाता है, हमारे ध्यान में लाए गए किसी अन्य परीक्षा नियमों में या विज्ञापन में बताए गए किसी भी शर्त, निर्देशों में परिलक्षित नहीं होती है, जिसमें अपीलकर्ता-आरपीएससी के विद्वान वकील द्वारा भारी भरोसा किया गया अपीलकर्ता-

आरपीएससी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब के साथ संलग्न अनुबंध आर-1 भी शामिल है।

13. रिट याचिका में, प्रतिवादी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह सुबह 9:00 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। जवाब में, अपीलकर्ता-आरपीएससी का रुख यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने सुबह 9:45 बजे परीक्षा केंद्र में कार्यालय में संपर्क किया। अपीलकर्ता कोई भी रजिस्टर पेश करने में विफल रहा है जो प्रतिवादी संख्या 1 सहित उम्मीदवारों की उपस्थिति को समय के साथ दर्ज करता है कि उसने सुबह 9:45 बजे परीक्षा के लिए रिपोर्ट किया था। इसलिए, इस न्यायालय के पास प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए गए बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यदि, अपीलकर्ता के अनुसार भी, प्रतिवादी संख्या 1 परीक्षा से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दे रहा था और यही प्रतिवादी संख्या 1 को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने का मुख्य कारण था।

इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना खुद का लेखक लाने का फैसला किया था, हमारे उपरोक्त अवलोकनों के मद्देनजर, बस और उचित हैं।

14. हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1, जो एक दिव्यांग व्यक्ति है, को केंद्र अधीक्षक द्वारा उचित संवेदनशीलता के साथ नहीं देखा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई रास्ता हो सकता था कि प्रतिवादी संख्या 1 परीक्षा में उपस्थित हो। अधिकारियों को लेखक की मदद से प्रतिवादी संख्या 1 को परीक्षा लिखने की अनुमति देने से कुछ भी नहीं रोका। विज्ञापन में किसी भी प्रावधान के अभाव में कि क्या एक विकलांगता वाले उम्मीदवार ने अपना खुद का लेखक लाया है या लेखक की सुविधा मांगी है, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र का उत्पादन आवश्यक होगा, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो परीक्षा से ठीक पहले विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार पर विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर देना पूरी तरह से अवैध और क्रूर है।

रिट याचिकाकर्ता भी अदालत में मौजूद है और वह स्पष्ट रूप से नेत्रहीन है। उसके प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि वह 100% दृष्टि विकलांगता से पीड़ित है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे सामने जुर्माने के पहलू पर जोरदार ढंग से आग्रह किया है कि अधिनियम की योजना के अनुसार, पहला उल्लंघन केवल ₹10,000/- का जुर्माना लगाता है, वह भी ऐसे मामले में, जहां अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रदान किए गए अपराध का कमीशन साबित होता है। यह केवल उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर है कि जुर्माना/जुर्माना ₹5,00,000/- तक जा सकता है।

16. यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध के कमीशन के प्रमाण से संबंधित आदेश से उत्पन्न होने वाले मामले से निपट रहा है। यह एक ऐसा मामला है जहां यह न्यायालय पाता है कि संवेदनशीलता की कमी और विकलांगता वाले उम्मीदवार के साथ अनुचित व्यवहार के कारण, उसे सार्वजनिक रोजगार की तलाश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया था। एक विकलांग व्यक्ति के अधिकारों के प्रति उचित व्यवहार और अनादर से इनकार एक गंभीर मामला है और इससे भी अधिक, जब यह सार्वजनिक संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई गलती का परिणाम है। अधिनियम का विधायी इरादा विकलांगता वाले व्यक्तियों को कानून के तहत सूचीबद्ध सभी सुविधाएं प्रदान करने का है जिसमें आरक्षण और अन्य लाभ शामिल हैं और विकलांगता वाले व्यक्तियों से निपटने वाले सार्वजनिक संस्थानों के अधिकारी तकनीकी गलती खोजने और अति-तकनीकी आधार पर उनके वैध अधिकार से इनकार करने के बजाय विकलांगता वाले व्यक्तियों को उचित उपचार और सुविधाएं देने के लिए कानून के तहत कर्तव्यबद्ध और बाध्य हैं। यही वर्तमान मामले में हुआ है और विद्वान एकल न्यायाधीश को आरपीएससी पर जुर्माना लगाने के लिए प्रेरित किया।

यह तर्क कि यदि कुछ गलत किया गया है, तो केंद्र अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, आरपीएससी को एक परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है, विशेष रूप से जब विकलांग श्रेणी से संबंधित एक उम्मीदवार ने सार्वजनिक रोजगार का एक अवसर खो दिया है क्योंकि उन लोगों द्वारा

की गई अवैधताओं के कारण जो परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में शामिल थे, आरपीएससी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे।

17. इसलिए, हम इस विचार से हैं कि वर्तमान मामला विकलांगता वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने के मामलों में असंवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी और विकलांगता वाले व्यक्तियों के साथ सीधे व्यवहार करने वालों को ठीक से प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, आरपीएससी को इस संबंध में सभी संस्थानों और संबंधित अधिकारियों को व्यापक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी लोगों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाएं ताकि वर्तमान मामले में बनाई गई स्थिति भविष्य में दोहराई न जाए।

18. प्रतिवादियों को उपरोक्त अवलोकनों और निर्देशों के अधीन, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

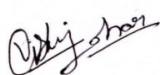
19. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायाधीश

मनोज नरवानी /59

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़